

INBRIEF



GAIL signs initial pact to set up 1 GW projects in Karnataka

GAIL (India) Ltd. has signed an MoU with the Karnataka government to explore setting up of renewable energy projects of up to 1 gigawatt (GW) in the State. Under the MoU, the Government of Karnataka would facilitate GAIL to obtain necessary permissions, registrations, approvals, clearance, etc., from the departments concerned of the state, as per the prevailing policies and rules and regulations of the state government, the company said in a statement. PTI



GAIL signs initial pact to set up 1 GW projects in Karnataka

GAIL (India) Ltd. has signed an MoU with the Karnataka government to explore setting up of renewable energy projects of up to 1 gigawatt (GW) in the State. Under the MoU, the Government of Karnataka would facilitate GAIL to obtain necessary permissions, registrations, approvals, clearance, etc., from the departments concerned of the state, as per the prevailing policies and rules and regulations of the state government, the company said in a statement. PTI

GAIL, K'taka sign MoU to set up 1 GW renewable energy project



GAIL (India) Ltd has signed a memorandum of understanding (MoU) with the Karnataka government to explore the setting up of renewable energy projects of up to 1 gigawatt (GW) in the state. The MoU was signed in Bengaluru on May 9, 2025 in the presence of M.B. Patil, Minister for Large and Medium Industries and Infrastructure Development, Government of Karnataka, and K. J. George, Minister for Energy, Government of Karnataka, by Dr. S. Selvakumar, Principal Secretary, Commerce &

Industries Department, Government of Karnataka and Parivesh Chugh, Executive Director (SD & Renewables), GAIL. "Under the MoU, the Government of Karnataka would facilitate GAIL to obtain necessary permissions/registrations/approvals/clearance/incentives, etc., from the concerned departments of the state, as per the prevailing policies/rules and regulations of the state government. GAIL intends to set up renewable energy projects of up to 1 GW within a period of five years," the company said in a statement.

GAIL inks MoU to set up 1 GW renewable power projects in Karnataka



NEW DELHI: State-owned GAIL (India) Ltd has signed a memorandum of understanding (MoU) with the Karnataka government to explore the setting up of renewable energy projects of up to 1 gigawatt (GW) in the state.

“Under the MoU, the Government of Karnataka would facilitate GAIL to obtain necessary permissions/registrations/approvals/clearance/ incentives, etc., from the concerned departments of the state, as per the prevailing policies/rules and regulations of the state government. GAIL intends to set up renewable energy projects of up to 1 GW within a period of five years,” the company said in a statement.

The company is targeting net-zero carbon emissions for its operations by 2035, and renewable energy projects are

part of the plan for achieving that goal.

The MoU was signed in Bengaluru on May 9, 2025, in the presence of MB Patil, Karnataka’s Minister for Large and Medium Industries and Infrastructure Development, and KJ George, Karnataka’s Minister for Energy, by S Selvakumar, Principal Secretary in the state’s Commerce & Industries Department, and GAIL Executive Director (SD & Renewables) Parivesh Chugh.

“We welcome GAIL’s strategic interest in Karnataka. This MoU reaffirms our commitment to facilitating clean energy investments while driving industrial growth. Karnataka’s policy ecosystem, skilled workforce, and land availability make it a natural partner for companies focused on sustainability,” Patil added. *MP05T*

गेल ने कर्नाटक में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए समझौता किया

नई दिल्ली, 10 मई (एजेंसी): सार्वजनिक क्षेत्र की गैस उपयोगिता कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कर्नाटक सरकार के साथ राज्य में एक गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स) की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने कहा, "एम.ओ.यू. के तहत कर्नाटक सरकार गेल को राज्य सरकार की मौजूदा नीतियों/नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य के संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति/पंजीकरण/अनुमोदन/मंजूरी/प्रोत्साहन आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी। गेल का इरादा 5 साल के भीतर एक गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का है।" हालांकि, गेल ने परियोजना के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया। कंपनी 2035 तक

अपने परिचालन के लिए शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बना रही है।

और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना का हिस्सा हैं। समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर 9 मई को बेंगलुरु में कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम.बी. पाटिल और कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज की उपस्थिति में राज्य के वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस. सेल्वाकुमार और गेल के कार्यकारी निदेशक (एस.डी. और नवीकरणीय) परिवेश चुघ ने किए। इस मौके पर पाटिल ने कहा, "हम कर्नाटक में गेल की रणनीतिक रुचि का स्वागत करते हैं। यह समझौता ज्ञापन औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ ऊर्जा निवेश को सुविधाजनक बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।"



गैल ने ऊर्जा परियोजनाओं में किया समझौता

5 साल में 1 गीगावाट तक का नव ऊर्जा संयंत्र बनेगा

एजेसी नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र की गैस उपयोगिता कंपनी गैल (इंडिया) लिमिटेड ने कर्नाटक सरकार के साथ राज्य में एक गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने कहा कि कर्नाटक सरकार गैल को राज्य सरकार की मौजूदा नीतियों और नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य के संबंधित विभागों से अनुमति, पंजीकरण, मंजूरी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी।



मंत्रियों की उपस्थिति में साइन किए गए

कंपनी 2035 तक अपने परिचालन के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बना रही है। एमओयू पर हस्ताक्षर बेंगलुरु में बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल और ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज की उपस्थिति में अधिकारियों के बीच किया गया।

गेल ने कर्नाटक में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए समझौता किया

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र की गैस उपयोगिता कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कर्नाटक सरकार के साथ राज्य में एक गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, एमओयू के तहत, कर्नाटक सरकार गेल को राज्य सरकार की मौजूदा नीतियों/नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य के संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति पंजीकरण अनुमोदन मंजूरी प्रोत्साहन आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी। गेल का



इरादा पांच साल के भीतर एक गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का है। हालांकि, गेल ने परियोजना के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया। कंपनी 2035 तक अपने परिचालन के लिए शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बना रही है, और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना का

हिस्सा हैं। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नौ मई, 2025 को बेंगलुरु में कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल और कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज की उपस्थिति में राज्य के वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सेल्वकुमार और गेल के कार्यकारी निदेशक (एसडी और नवीकरणीय) परिवेश चुघ ने किए। इस मौके पर पाटिल ने कहा, हम कर्नाटक में गेल की रणनीतिक रुचि का स्वागत करते हैं। यह समझौता ज्ञापन औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ ऊर्जा निवेश को सुविधाजनक बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

101 परिवारों को मिला पाइप गैस कनेक्शन, सिलचर में सीएनजी स्टेशन की शुरुआत

वैभव न्यूज ■ गुवाहाटी

असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के लोगों को शनिवार को पहली बार पाइप रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा मिली। इसके पहले चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने किया, जिसके तहत 101 घरों को पाइप रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए। शर्मा ने सिलचर में बराक घाटी के पहले सीएनजी स्टेशन का भी उद्घाटन किया और गुवाहाटी से सटे इलाकों बैहाटा चारियाली, हाजो, सुआलकुची और रंगिया में पाइप से गैस उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक कार्य का शुभारंभ किया। यह परियोजना पूर्वी भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड (पीबीजीपीएल) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और गेल गैस लिमिटेड



(गेल गैस) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। पीबीजीपीएल को कामरूप (महानगर), कामरूप, कछार, हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस अवसर पर शर्मा ने कहा, आज, हम 101 परिवारों को कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। नेटवर्क का विस्तार किया जा सकता है क्योंकि बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है। मैं गुवाहाटी के लोगों से पाइप से रसोई गैस कनेक्शन की

सदस्यता लेने का आग्रह करता हूं क्योंकि यह सुरक्षित और किफायती दोनों है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सिलचर में सीएनजी स्टेशन का खुलना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और कहा कि बराक घाटी के अन्य दो जिलों हैलाकांडी और श्रीभूमि में भी जल्द ही इसी तरह के डिपो खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अब करीब 23 सीएनजी स्टेशन हैं, लेकिन और भी स्टेशन खोले जाने की जरूरत है।